सुभाषित *प्रसन्नता और दुःख किसीके भी जीवनमें आते-जाते रहते हैं और ऐसा नहीं हो सकता ही कि लगातार सिर्फ प्रसन्नता ही बनी रहे।* ❐ **महर्षि वाल्मिकी**

खुदरा महंगीमें वृद्धि

खुदरा महंगीमें वृद्धि गम्भीर चिन्ताका विषय है। इससे आमजन जीवनपर आर्थिक बोझ बढ़ा है। उपलब्ध आंकड़ोंके अनुसार खुदरा महंगी २३ महीनेके उच्च स्तरपर पहुंच गयी है। खाद्य पदार्थों, ऊर्जा और आयातित वस्तुओंकी कीमतें बढ़नेसे भविष्यके लिए जोखिम बढ़ गया है। वैसे मौजूदा महंगी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के २-६ प्रतिशतके सहनशीलताके दायरेमें है। अगस्त, २०२६ में खुदरा महंगी ४.८२ प्रतिशत रही, जबकि उपभोक्ता खाद्य महंगी ५.९५ प्रतिशत थी। सितम्बरके ताजे आंकड़ोंके जारी होनेसे पूर्व अर्थशास्त्रियोंके सर्वेक्षणमें अनुमान लगाया है कि यह ५.४० प्रतिशत हो सकती है, जो अगस्तमें ४.८२ प्रतिशतसे काफी अधिक है। इसका सबसे बड़ा कारण खाद्य और ऊर्जाकी कीमतोंमें वृद्धि माना जा रहा है। इसलिए कहा जा सकता है कि महंगी फिर सिर उठाने लगी है। भारतमें महंगीका सबसे संवेदनशील हिस्सा खाद्य पदार्थ है। खुदरा महंगी (सीपीआई) में खाद्य और पेय पदार्थोंका भार लगभग ४० प्रतिशत है। इसलिए सब्जियां, दालें, अनाज, खाद्य तेल, दूध और फल जैसी वस्तुओंकी कीमतोंमें वृद्धि सीधे खुदरा महंगीको प्रभावित करती है। एक अतिरिक्त समस्या कमजोर मानसूनकी है। जून-सितम्बर २०२६ का मानसून सामान्यसे लगभग १२.६ प्रतिशत कम रहा, जिससे फसल उत्पादन और ग्रामीण आयको लेकर चिन्ता अवश्य बढ़ी है। इसका प्रभाव केवल किसानोंपर नहीं पड़ेगा, उत्पादन कम होनेपर आगामी महीनोंमें अनाज, दाल, सब्जियों और अन्य कृषि उत्पादोंकी कीमतोंपर दबाव बढ़ सकता है। महंगीके मोरचेपर दूसरी बड़ी चुनौती कच्चे तेलकी कीमत है। पश्चिम एशियामें तनावके कारण कच्चा तेल सौ डालर प्रति बैरलके ऊपर बना हुआ है। इससे भारतमें परिवहन, उर्वरक, बिजली, प्लास्टिक, रसायन और अनेक औद्योगिक उत्पादोंपर महंगीकी मार पड़ी है। भारतीय रुपयेकी कमजोरी समस्याको और बढ़ाती है। हालके दिनोंमें रुपया लगभग ९७ रुपये प्रति डालरके करीब पहुंच गया था। आरबीआईके हस्तक्षेपके बाद १२ अक्तूबरको इसमें लगभग एक प्रतिशतकी मजबूती आयी है,लेकिन आयातित महंगीका जोखिम अभी समाप्त नहीं हुआ है। भारतके सामने महंगा तेल और कमजोर रुपया दोनों बड़ा जोखिम है। महंगीके दबावको देखते हुए ही रिजर्व बैंकने सात अक्तूबरको रेपो दर २५ आधार अंक बढ़ाकर ५.५० प्रतिशत कर दिया। चार वर्षोंके बाद यह वृद्धि हुई है। महंगीपर नियंत्रणके लिए मौद्रिक नीति और आपूर्ति-प्रबन्धन दोनोंको साथ चलाना होगा। खाद्य भण्डारण और आपूर्ति व्यवस्थाको भी मजबूत बनाना होगा। पर्याप्त बफर स्टाक आवश्यक है। जमाखोरीपर कड़ी काररवाई करनी होगी। आरबीआईको महंगी दर चार प्रतिशतपर लानेका प्रयास करना होगा तभी जनताको राहत मिल पायेगी।

नेपालमें फिर बाढ़से तबाही

अभी करीब डेढ़ माह पूर्व ही नेपालके भोटेकाशी और त्रिशूली नदियोंमें आयी विनाशकारी बाढ़से लोग उबर भी नहीं पाये थे कि रविवार सुबह बूढ़ी गंडक नदीमें अचानक आयी बाढ़ने एक बार फिर भारी तबाही मचायी है। इस बाढ़में देखते ही देखते ४५ मकान और छह पुल नदीमें समा गये। भूस्खलन और बाढ़से जलविद्युत परियोजनाओंको भी भारी नुकसान पहुंचा है। राहतकी बात यह है कि इस आपदामें कोई हताहत नहीं हुआ है लेकिन पांच लोग लापता बताये जाते हैं। सेनाने तत्काल मोरचा सम्भालते हुए नौ विदेशियों समेत ८२ लोगोंको सुरक्षित स्थानपर पहुंचाया है। तटवर्ती इलाकोंके लोगोंको ऊंचाई वाले स्थानोंपर जानेको कहा गया है। नदीका जलस्तर लगातार बढ़ रहा है जिससे लोग सहमे हुए हैं। बचाव अभियान, राहत सामग्री पहुंचाने और लोगोंको सुरक्षित स्थानपर ले जाने लिए हेलीकाप्टर तैनात किये गये हैं। उल्लेखनीय है कि बीते २६ अगस्तको दो प्रमुख नदियों भोटेकाशी और त्रिशूलीमें आयी प्रलंयकारी बाढ़में १४०० से अधिक लोगोंकी मौत हुई थी और पांच हजारसे अधिक लोग अब भी लापता हैं। इस बार जिलेके उत्तरी हिस्सेमें आयी बाढ़, जिसके और विकराल होनेकी आशंका है, को देखते हुए स्थानीय लोग दहशतमें हैं और अफरा-तफरीका माहौल है। अचानक आयी इस बाढ़से नेपाल सीमासे सटे भारतके बिहार राज्यमें बाढ़का खतरा बढ़ रहा है। बिहार सरकार और प्रशासनको पूरी तरह सतर्क रहना होगा और किसी भी स्थितिसे निबटनेके लिए पहलेसे ही पूरी तैयारी करनी होगी। सीमावर्ती लोगोंको भी सुरक्षित स्थानोंपर पहुंचानेकी व्यवस्था होनी चाहिए। बिहारपर बाढ़का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि बूढ़ी गंडकी आगे चलकर त्रिशूली नदीसे मिलती है फिर दोनोंका पानी देवघरके पास नारायणी नदीमें पहुंचता है। यही नदी भारतमें गंडकके नामसे बिहारमें आती है और गंगा नदीमें मिल जाती है। यदि पानीका बहाव बढ़ता है तो बिहारके कई जिले बाढ़की चपेटमें आ जायंगे। इसलिए सतर्क रहना होगा और स्थितिपर लगातार निगाह रखनी होगी।

लोक संवाद

सामान्य जीवन भी जीते हैं कैंसर रोगी

महोदय,-कैंसर गम्भीर बीमारी है, जिसका समयपर पता लगना और सही इलाज शुरू होना बेहद जरूरी है। आधुनिक चिकित्सामें सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी जैसी तकनीकोंकी मददसे कई प्रकारके कैंसरका इलाज किया जाता है। कई मरीज इलाजके बाद सामान्य जीवन भी जीने लगते हैं। हालांकि कुछ मामलोंमें इलाज पूरा होनेके महीनों या सालों बाद कैंसर दोबारा सामने आ सकता है। ऐसी स्थितिको कैंसरकी पुनर्वति कहा जाता है। ऐसेमें सवाल उठता है कि जब मरीजका इलाज पूरा हो चुका होता है तो कैंसर दोबारा कैसे हो जाता है। क्या इसकी वजह इलाज अधूरा रह जाना है या खानपान और लाइफस्टाइलकी गलतियां भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकती हैं। जानते हैं कि इलाजके बाद भी कैंसर लौटनेके पीछे क्या कारण हो सकते हैं और मरीजोंको किन बातोंका ध्यान रखना चाहिए। कैंसरका इलाज पूरा होनेका मतलब हमेशा यह नहीं होता कि शरीरकी हर कैंसर कोशिका खत्म हो गयी है। कई बार इलाजके बाद भी कुछ बेहद छोटी कैंसर कोशिकाएं शरीरमें बची रह सकती हैं, जिनका सामान्य जांचमें पता लगाना मुश्किल होता है। समयके साथ ये कोशिकाएं दोबारा बढ़ सकती हैं और कैंसरकी वापसीका कारण बन सकती हैं। कैंसरके दोबारा होनेकी सम्भावना इस बातपर भी निर्भर करती है कि कैंसर किस प्रकारका था, किस स्टेजमें उसका पता चला, उसकी कोशिकाओंकी विशेषताएं क्या थीं और इलाजके प्रति उनका रिस्पॉन्स कैसा रहा। इसलिए कैंसरके इलाजके बाद दोबारा बीमारी होनेका मतलब यह जरूरी नहीं है कि इलाज गलत हुआ था या डाक्टरसे कोई गलती हुई थी। कुछ मामलोंमें निर्धारित इलाज पूरा न हो पाना कैंसरके नियंत्रणको प्रभावित कर सकता है। उदाहरणके लिए डाक्टर द्वारा सुझाये गये कीमोथेरेपीके सभी चक्र पूरे न करना या जरूरी दवाएं बीचमें बंद कर देना उपचारके परिणामोंपर असर डाल सकता है। कैंसरको समझनेके लिए शरीरमें होने वाले बदलावों और जीवनशैलीपर भी ध्यान देना चाहिए। कैंसरके इलाजके दौरान और उसके बाद खानपानकी अहम भूमिका होती है। संतुलित आहार शरीरको जरूरी पोषक तत्व देने, मांसपेशियोंकी ताकत बनाये रखने और इलाजके बाद रिकवरीमें मदद करता है। लेकिन किसी एक खाद्य पदार्थको खाने या छोड़नेसे कैंसर दोबारा होनेका खतरा पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। इसी तरह यह दावा करना भी सही नहीं है कि किसी खास भोजनकी वजहसे ही कैंसर वापस आ गया। इलाजके बाद मरीजको अपनी जरूरतके अनुसार संतुलित आहार लेना चाहिए। इसमें फल, सब्जियां, साबुत अनाज और प्रोटीनके उपयुक्त स्रोत शामिल किये जा सकते हैं। मरीजकी स्थितिके अनुसार आहारमें बदलावके लिए डाक्टर या योग्य डाइटीशियनकी सलाह लेना बेहतर है। कुछ जीवनशैली संबंधी आदतें कैंसर होने या कुछ प्रकारके कैंसरका जोखिम बढ़नेसे जुड़ी हैं। इलाजके बाद स्वस्थ जीवनशैली अपनाना मरीजकी सेहत, शारीरिक क्षमता और जीवनकी गुणवत्ताके लिए फायदेमंद है। कैंसरके इलाजके बाद शरीरमें होने वाले हर बदलावका मतलब कैंसरकी वापसी नहीं होता। कई लक्षण सामान्य बीमारियों या इलाजके दुष्प्रभावोंके कारण भी हो सकते हैं। फिर भी कुछ बदलाव लगातार बने रहें या बढ़ते जायं तो डाक्टरसे संपर्क करना चाहिए। सही कारण जाननेके लिए चिकित्सकीय जांच जरूरी है। -**मोनिका शर्मा, वाया ईमेल।**

भारत और चीनके बीच सीमा संघर्ष

चीनके विदेश मंत्रालयके अभिलेख २००४ से २०१२ तक सीमित समयके लिए सार्वजनिक किये गये थे। इन दस्तावेजोंका समूह १९६१ से १९६५ के बीचका है। इन्हें २००८ में सार्वजनिक किया गया। हालांकि इनमेंसे काफी हिस्सेको हटा दिया गया था, परन्तु १९६२ के भारत-चीन सीमा संघर्षसे पहलेकी घटनाएं इसमें शामिल थीं।

❐ **श्याम सरन**

चीनके विदेश मंत्रालयके आर्काइव (अभिलेख) दस्तावेजोंमें काफी हिस्सेको हटा दिया गया था। उन अभिलेखोंतक पहुंच रखने वाले स्रोतोंकी रिपोर्ट्स लोगोंने पढ़ी हैं। मैं इस लेखमें २२ और २३ जुलाई, १९६२ को जिनेवामें भारतके तत्कालीन रक्षामंत्री वी. के. कृष्ण मेनन और चीनके उपप्रधान मंत्री चेन यी की बैठकोंपर ध्यान केन्द्रित करना चाहता हूं। दोनों नेताओंकी बातचीत इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि इन प्रस्तावोंपर आगे बातचीत की गयी होती तो संभव है कि बादमें हुआ सीमा युद्ध टाला जा सकता था। कृष्णा मेननकी टिप्पणियां यहां संक्षेपमें दे रहे हैं- मेननने कथित रूपसे चेन यी से कहा कि यदि भारत-चीन सीमा समस्या नेहरूकी मौतसे पहले हल नहीं हुई तो यह और आगे खिंच जायगी। दोनों देशोंके बीच विवादकी शुरुआत अक्साई रोडसे हुई थी इसलिए इस समस्याका समाधान भी इसी सड़कसे शुरू होना चाहिए। हमें पश्चिमी क्षेत्रमें एक नयी सीमा रेखा खींचनेसे शुरुआत करनी चाहिए। यानी संबंधित क्षेत्र जिसमें सड़क और उसके दोनों ओरका इलाका शामिल है उसे चीनके क्षेत्रके रूपमें निर्धारित किया जा सकता है और इसके बदले चीन पूर्वी क्षेत्रमें भारतको कुछ ऐसा इलाका दे सकता है जिसे सभी लोग चीनी क्षेत्र मानते हैं।

कहा गया कि पूर्वी क्षेत्रमें चीन पहले ही लोंगजूसे पीछे हट चुका है और भारतने शांतिकी भावनाके तहत वहां दोबारा प्रवेश नहीं किया है। इसलिए अब पूर्वी क्षेत्रमें कोई समस्या नहीं रह गयी है। यदि सीमा विवादका समाधान इस तरह किया जा सकता है तो दोनों देश ५० वर्षोंके लिए मैत्री संधिपर हस्ताक्षर कर सकते हैं और व्यापार शुरू कर सकते हैं। चेन यी ने इस प्रस्तावको यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मेननके प्रस्तावका मतलब यह होगा कि चीनको पूर्वमें अपनी ९०,००० वर्ग किलोमीटरकी भूमि छोड़नी होगी और पश्चिममें भी अपने कुछ क्षेत्रसे हाथ धोना होगा। यह चीनको स्वीकार्य नहीं था। एक अन्य संदर्भके अनुसार भारतको बदलेमें दिया जाने वाला चीनी क्षेत्र चुम्बी घाटी था। यह चीनी क्षेत्रका एक ऐसा हिस्सा है जो उत्तर-पूर्वी भारतकी ओर आगेतक फैला हुआ है। इसके बाद मेननने प्रस्ताव रखा कि सीमापर टकरावको रोकनेके लिए इसे एक अस्थायी व्यवस्था स्वीकार की जा सकती है, तबतक दोनों पक्ष अपनी-अपनी मौजूदा स्थितियोंपर कायम रहें। इसके बाद उन्होंने इन अस्थायी व्यवस्थाओंका काफी विस्तारसे खाका प्रस्तुत किया। इससे संकेत मिलता है कि इन प्रस्तावोंपर भारतकी ओर से उच्च स्तरपर विचार-विमर्श किया गया होगा। अभिलेखोंके अनुसार मेननने निम्नलिखित प्रस्ताव रखा था।

दोनों पक्ष इस बातपर सहमत हो सकते हैं कि पश्चिमी क्षेत्रके विवादित इलाकोंमें दोनों देशोंके सीमा सुरक्षा बलोंको स्वतंत्र रूपसे अपनी चौकियां स्थापित करनेकी अनुमति होगी। दोनों पक्षोंकी सुरक्षा चौकियोंमें तैनात बलोंकी संख्यापर स्पष्ट सीमाएं होंगी। किसी एक पक्षकी चौकीपर तैनात बलोंकी संख्या दूसरे पक्षकी चौकीकी तुलनामें कई गुना अधिक नहीं होनी चाहिए और किसी भी पक्षको दूसरे पक्षपर हमला नहीं करना चाहिए। इसके अलावा दोनों पक्षोंकी चौकियोंके बीच एक-दो मीलकी दूरी बनाये रखी जानी चाहिए। दोसे तीन साल बाद इसकी समीक्षा की जा सकती है। चेन यी ने मेननके प्रस्तावोंपर आपत्तियां तो जतायी लेकिन साथ ही संघर्षको टालनेकी इच्छा भी दिखायी। उन्होंने एक और बैठक करनेका प्रस्ताव रखा। इस बीच चेन यी ने यकीनन चीनी नेताओंसे विचार-विमर्श किया होगा। २३ जुलाईकी दूसरी बैठकमें उन्होंने एक बार फिर मेननके प्रस्तावोंपर अपनी आपत्तियां व्यक्त कीं लेकिन संघर्षसे बचनेके उपायके रूपमें अस्थायी व्यवस्थाओंपर विचार करनेकी इच्छा भी जतायी। उन्होंने कहा कि चीन और भारत दोनों ही युद्ध नहीं चाहते और यह दोनों पक्षोंके बीच एक साझा बात है। इसलिए दोनों पक्षोंकी पहली प्राथमिकता संघर्षसे बचनेके उपायोंपर चर्चा करना होगी।

इसके बाद उन्होंने यह प्रस्ताव रखा और यह बात अहम है कि वह और मेनन, चीन और भारतके बीच सीमापर टकरावको रोकनेके लिए हुई बातचीतपर जिनेवामें एक संयुक्त बयान जारी करें। बातचीतका समय और स्तर बादमें तय किया जा सकता था। इसके बाद मेनन सतर्क हो गये। शायद उन्हें लगा कि वे अपने अधिकार-क्षेत्रसे आगे बढ़कर बात कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि दोनों मंत्रियोंको अस्थायी व्यवस्थाओंके संबंधमें हुई अपनी बातचीतकी जानकारी अपनी-अपनी सरकारोंको देनी चाहिए और संयुक्त विज्ञप्ति दोनों सरकारोंकी ओरसे जारी की जा सकती है। विज्ञप्तिमें जिनेवामें हुई उनकी बातचीतका उल्लेख किया जा सकता था और सीमापर टकरावसे बचनेके लिए संवाद जारी रखनेपर सहमति व्यक्त की जा सकती थी।

दिल्ली लौटनेके छह दिन बाद मेननने नेहरू और मंत्रिमंडलको इसकी जानकारी दी। इस चर्चाका कोई रिकॉर्ड नहीं है। यद्यपि एक समाचार रिपोर्टके अनुसार फिलहाल आगेकी बातचीतकी सम्भावनाको खारिज कर दिया गया था और मंत्रियोंको लगा था कि गतिरोध आगे भी जारी रहेगा। हम जानते हैं कि चीन नीतिको लेकर नेहरू और मेनन दोनोंको कांग्रेस पार्टीके भीतर और विपक्ष, दोनोंकी ओरसे काफी राजनीतिक विरोधका सामना करना पड़ रहा था। यह केवल अटकल ही लगाया जा सकता है कि क्या 'अस्थायी व्यवस्थाओं' पर प्रस्तावित बातचीत युद्धको टाल सकती थी। उल्लेखनीय है कि चेन यी ने संघर्ष टालनेके लिए मेनन द्वारा उपलब्ध कराये गये अवसरको तुरन्त समझ लिया था। अन्य स्रोतोंसे हमें पता चलता है कि अगस्तमें हुई पोलित ब्यूरोकी एक बैठकमें माओने दबाव डालकर भारतके साथ युद्धमें जानेका फैसला कराया था। इस फैसले का 'कुछ कॉमरेड' ने विरोध किया था। उनका तर्क था कि १९५९-६२ के ग्रेट लीप फॉरवर्ड और उसके बाद पड़े भयंकर अकालकी त्रासदीके बाद चीन गम्भीर आर्थिक संकटसे जूझ रहा था। अमेरिका और सोवियत संघ, दोनोंकी शत्रुताका भी उसे सामना करना पड़ रहा था। ऐसे समयमें भारतको भी अपना दुश्मन बना लेना चीनके हितमें नहीं होगा। लेकिन माओने उनकी आपत्तियोंको खारिज कर दिया और एक विवरणके अनुसार इस समूहके कुछ सदस्योंको 'दक्षिणपंथी अवसरवादी' तक कहकर आलोचना की। यदि मेनन और चेन यी ने वह संयुक्त विज्ञप्ति जारी कर दी होती या यदि नेहरूके मंत्रिमंडलने मेननकी पहलको मंजूरी दे दी होती तो संभव है कि १९६२ के सीमा युद्धकी ओर ले जाने वाली घटनाओंकी दिशा कुछ अलग होती।

भारत और चीनके बीच विवादकी शुरुआत अक्साई रोडसे हुई थी इसलिए इस समस्याका समाधान भी इसी सड़कसे शुरू होना चाहिए। हमें पश्चिमी क्षेत्रमें एक नयी सीमा रेखा खींचनेसे शुरुआत करनी चाहिए। यानी संबंधित क्षेत्र जिसमें सड़क और उसके दोनों ओरका इलाका शामिल है उसे चीनके क्षेत्रके रूपमें निर्धारित किया जा सकता है और इसके बदले चीन पूर्वी क्षेत्रमें भारतको कुछ ऐसा इलाका दे सकता है। पूर्वी क्षेत्रमें चीन पहले ही लोंगजूसे पीछे हट चुका है और भारतने शांतिकी भावनाके तहत वहां दोबारा प्रवेश नहीं किया। इसलिए अब पूर्वी क्षेत्रमें कोई समस्या नहीं रह गयी है।

स्वच्छ पेयजलके बिना कैसा विकास

पेयजलसे लेकर जल संरक्षणकी योजनाओंपर अत्यंत शिथिलता बरती जा रही है। दो वर्ष पूर्व आम बजटमें तमाम प्रावधान किये गये थे, लेकिन इस बजटमें वे सिरेसे गायब हैं। देशको विकसित राष्ट्र बनानेमें जल संसाधनका अत्यन्त महत्व है।

❐ **योगेंद्र**

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीने अपने सार्वजनिक जीवनके २५ साल पूरे होनेपर आयोजित कार्यक्रमको एक घंटेतक संबोधित करते हुए कहा कि जबतक भारत विकसित नहीं होता, तबतक न थकूंगा, न रुकूंगा। इस नारेका १९ बार जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारतको २०४७ तक हर हालतमें विकसित देश बनाना है। निश्चित तौरपर भारतको विकसित देश बनना ही चाहिए। सवाल यह है कि क्या तबतक भारतके करोड़ों लोग प्यासे रहेंगे। उन्हें पर्याप्त और शुद्ध पानीके लिए क्या भारतके विकसित होनेतक इंतजार करना पड़ेगा। क्या देशके लोगोंकी प्यास और दूषित पेयजलसे जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओंको तबतकके लिए रोका जा सकता है। विकसित भारतका सपना देखनेमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इससे पहले केन्द्र और राज्योंकी सरकारोंको यह खुलासा करना चाहिए कि देशके लोगोंको गुणवत्तायुक्त पर्याप्त पीनेका पानी कबतक उपलब्ध हो जायगा। इसके लिए देशकी राष्ट्रीय नीति क्या है। इस मुद्देपर कोई बोलनेको तैयार नहीं है। इसके बारेमें चर्चा करते ही देशके विकास और विकसित भारतके सपनेपर सवालिया निशान लग जाते हैं। देशके सत्तारूढ़ दलों और विपक्षी दलोंके नेता ऐसी जमीनी जरूरतोंके मुद्दोंसे मुंह चुराते हैं। पेयजल जैसी समस्याओंसे निबटनेके लिए सरकारोंके पास दूरदृष्टि और योजनाएं नहीं हैं। यदि लगातार एक या दो बार देशमें मानसून मेहरबान न हो तो देशमें पीनेके पानीका हाहाकार मचने लगता है।

देशमें पेयजल संकट अभीसे गहराने लगा है, जबकि अभी मानसूनकी विदाई हुई है। महाराष्ट्रमें राज्य सरकारने १६ अक्तूबरसे सभी शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायोंमें कमसे कम दस प्रतिशत जल कटौती लागू करनेका निर्णय लिया है। राज्यके जालना जिलेमें बांधमें केवल दो प्रतिशत पानी बचा है। नौबत यहांतक आ गयी है कि प्रशासनको पानीकी चोरी रोकनेके लिए पुलिस और राजस्व विभागकी टीमोंके साथ रातमें भी निगरानी और गश्त करनी पड़ रही है। इस बार मानसूनमें बारिशकी करीब १२-१३ प्रतिशतकी कमीके कारण देशके दूसरे राज्योंकी हालत भी महाराष्ट्र जैसी होनेसे इनकार नहीं किया जा सकता। देशके कई राज्योंमें कम बारिशका असर अब जलाशयोंपर दिख रहा है। १ अक्तूबरतक देशके प्रमुख जलाशयोंमें ७१.८४ फीसदी पानी था। पिछले साल इसी समय यह ९०.३१ फीसदी था, जबकि सामान्य स्तर ८१.७९ फीसदी है। अर्थात् इस बार जलाशयोंमें पानी पिछले सालके मुकाबले काफी कम है। देशभरमें इस बारका मानसून १३वां सबसे सूखा सीजन रहा। पिछले ११ सालोंमें यह सबसे कम बारिश वाला मानसून रहा है। हालांकि सीजन खत्म होनेसे पहले हुई तेज बारिशके कारण बारिशकी कमीमें २.५ फीसदीका सुधार हुआ। मानसून २०२६ सीजन सामान्यसे १२.६ फीसदी कम बारिशके साथ खत्म हुआ। देशके ४३ फीसदी जिलोंमें २० से ७२ फीसदीतक कम बारिश हुई। सबसे ज्यादा पंजाबमें ४१ फीसदी कम बारिश हुई। राजस्थानमें करीब २२ फीसदी कमी दर्ज की गयी। इनके अलावा नौ राज्योंमें भी औसतसे कम बारिश हुई। पूर्वी भारतमें ओडिशामें सामान्यसे ३० फीसदी ज्यादा बारिश हुई, जबकि बारिशके लिए प्रसिद्ध पूर्वोत्तर राज्योंमें इस साल १९०१ के बाद सबसे कम बारिश दर्ज की गयी। पानीकी कमीका असर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, राजस्थान और तमिलनाडुमें ज्यादा दिख रहा है। कई इलाकोंमें खेतीके लिए पानी कम पड़ रहा है और फसलोंको भी नुकसान हो रहा है। आजादीके साठ वर्षोंके बाद भी देशकी एक-तिहाई जनताको पीनेके लिए स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं है। शायद यही कारण है कि प्रतिवर्ष जलजनित बीमारियोंके चलते १५ लाख बच्चे कालके गालमें समा जाते हैं और कामके अनगिनत घंटोंका नुकसान होता है। समस्या यह है कि केन्द्र एवं राज्य सरकारें पेयजल संकटको दूर करनेके लिए गम्भीर नहीं, जबकि वे इससे परिचित हैं कि आने वाले समयमें पानीके लिए युद्ध छिड़ सकते हैं। भारतमें पेयजल संकट बढ़ती आबादी और कृषिकी जरूरतोंके कारण भी गम्भीर होता जा रहा है। करीब ६५-७० प्रतिशत जल कृषि कार्योंमें खप जाता है। इसके अतिरिक्त उद्योगोंके संचालनमें भी जलका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। विडंबना यह है कि न तो उद्योग एवं कृषि क्षेत्रको अपनी आवश्यकताभर पानी उपलब्ध हो पा रहा है और न ही आम आदमीको। हमारे देशमें जल संकट जब-तब गम्भीर रूप ले लेता है। बात चाहे कावेरी जल विवादके कारण तमिलनाडु और कर्नाटकके बीचकी तनातनीकी हो अथवा यमुना जलके बंटवारेको लेकर दिल्ली एवं हरियाणाके बीचकी, ऐसे विवाद लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब तो जल बंटवारेको लेकर राजनीति भी होने लगी है और एक प्रांतके लोगोंको दूसरे प्रांतके लोगोंके समक्ष खड़ा करनेमें संकोच नहीं किया जा रहा है। इन दिनों होगेंक्काल पेयजल परियोजनाको लेकर तमिलनाडु और कर्नाटकके बीच यही हो रहा है। एक रिपोर्टके अनुसार देशके ६० करोड़ लोग पानीकी किल्लतसे जूझ रहे हैं, जबकि १६ करोड़ लोग गंदा पानी पी रहे हैं। शुद्ध पानीके लिए सरकार करोड़ों-अरबों रुपये खर्च कर रही है, लेकिन हालात बदसे बदतर होते जा रहे हैं।

देशके करीब नौ राज्योंमें पानीकी गुणवत्ता खराब है। नीति आयोगकी कम्पोजिट वॉटर मैनेजमेंट इंडेक्स रिपोर्टमें बताया गया कि भारतमें पानीकी वजहसे हर साल दो लाख लोगोंकी मौत हो रही है। साल २०३० तक यह स्थिति और विकराल हो जायगी जब देशकी लगभग ४० फीसदी आबादीके सामने पानीका संकट होगा। विकसित भारतके २०४७ के लक्ष्यतक देशमें पेयजलकी हालतका तो आकलन ही नहीं किया गया है। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वेके वैश्विक स्तरपर कुल पानीकी सालाना निकासी या खपतके मामलेमें भारत पहले पायदान नंबर-१ पर है। अत्यधिक आबादी और कृषि (सिंचाई) के कारण सबसे आगे है। वैश्विक जल गुणवत्ता सूचकांकमें भारत १२२ देशोंमेंसे १२०वें स्थानपर है। सुरक्षित पेयजल और जल गुणवत्ताके मामलेमें भारतकी गिनती दुनियाके सबसे निचले स्तरके देशोंमें होती है। पेयजलसे लेकर जल संरक्षणकी योजनाओंपर अत्यंत शिथिलता बरती जा रही है। दो वर्ष पूर्व आम बजटमें ऐसी योजनाओंके लिए तमाम प्रावधान किये गये थे, लेकिन इस बजटमें वे सिरेसे गायब हैं। देशको विकसित राष्ट्र बनानेमें जल संसाधनका उतना ही महत्व है जितना ऊर्जा और अन्य साधनोंका। जबतक ऐसी बुनियादी सुविधाओंका समाधान नहीं होगा, तबतक विकसित राष्ट्रका सपना एक छलावा ही साबित होगा।

आत्मबोध

माताकी आराधना

❐ **सदानन्द शास्त्री**

चैत्र या वासन्ती नवरात्रका प्रारम्भ चैत्र मास शुक्ल पक्षकी प्रतिप्रदासे होता है। चैत्रमें आने वाले नवरात्रमें अपने कुल देवी-देवताओंकी पूजाका विशेष प्रावधान माना गया है। वैसे दोनों ही नवरात्र मनाये जाते हैं। फिर भी इस नवरात्रको कुल देवी-देवताओंके पूजनकी दृष्टि से विशेष मानते हैं। भगवतीके नौ प्रमुख रूप (अवतार) हैं तथा प्रत्येक बार नौ-नौ दिन ही ये विशिष्ट पूजाएं की जाती हैं। इस कालको नवरात्र कहा जाता है। वर्षमें दो बार भगवती भवानीकी विशेष पूजा की जाती है। मान्यता है कि नवरात्रमें महाशक्तिकी पूजा कर श्रीरामने अपनी खोई हुई शक्ति पायी, इसलिए इस समय आदिशक्तिकी आराधनापर विशेष बल दिया गया है। मार्कण्डेय पुराणके अनुसार दुर्गा सप्तशतीमें स्वयं भगवतीने इस समय शक्ति-पूजाको महापूजा बताया है। कलश स्थापना, देवी दुर्गाकी स्तुति, सुमधुर घंटियोंकी आवाज, धूप-बत्तियोंकी सुगंध, यह नौ दिनोंतक चलने वाले साधना पर्व नवरात्रका चित्रण है। हमारी संस्कृतिमें नवरात्र पर्वकी साधनाका विशेष महत्व है। नवरात्रमें ईश-साधना और अध्यात्मका अद्भुत संगम होता है। आश्विन माहकी नवरात्रमें रामलीला, रामायण, भागवत पाठ, अखंड कीर्तन जैसे सामूहिक धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। यही वजह है कि नवरात्रके दौरान प्रत्येक इनसान एक नये उत्साह और उमंगसे भरा दिखाई पड़ता है। वैसे तो ईश्वरका आशीर्वाद हमपर सदा ही बना रहता है, किन्तु कुछ विशेष अवसरोंपर उनके प्रेम, कृपाका लाभ हमें अधिक मिलता है। पावन पर्व नवरात्रमें देवी दुर्गाकी कृपा, सृष्टिकी सभी रचनाओंपर समान रूपसे बरसती है। इसके परिणामस्वरूप ही मनुष्योंको लोक मंगलके क्रियाकलापोंमें आत्मिक आनन्दकी अनुभूति होती है। संस्कृत व्याकरणके अनुसार नवरात्रि कहना त्रुटिपूर्ण है। नौ रात्रियोंका समाहार, समूह होनेके कारणसे द्वन्द्व समास होनेके कारण यह शब्द पुलिंग रूप नवरात्रमें ही शुद्ध है। पृथ्वी द्वारा सूर्यकी परिक्रमाके कालमें एक सालकी चार संधियां हैं। उनमें मार्च एवं सितंबर माहमें पड़ने वाली गोल संधियोंमें सालके दो मुख्य नवरात्र पड़ते हैं। इस समय रोगाणु आक्रमणकी सर्वाधिक संभावना होती है। ऋतु संधियोंमें अक्सर शारीरिक बीमारियां बढ़ती हैं। अत: उस समय स्वस्थ रहनेके लिएए शरीरको शुद्ध रखनेके लिए और तन-मनको निर्मल और पूर्णत: स्वस्थ रखनेके लिए की जाने वाली प्रक्रियाका नाम नवरात्र है। नौ रात यानी नवरात्र नाम सार्थक है। यहां रात गिनते हैं, इसलिए नवरात्र यानी नौ रातोंका समूह कहा जाता है। रूपकके द्वारा हमारे शरीरको नौ मुख्य द्वारों वाला कहा गया है। इसके भीतर निवास करने वाली जीवनी शक्तिका नाम ही दुर्गा देवी है।

विपक्षमें बिखरावसे भाजपाको फायदा

❐ **राधा रमण**

देशमें कमरतोड़ महंगी, बढ़ती बेरोजगारी, आर्थिक दिवालियापनके हालात और पिछले १२ वर्षोंके दौरान १५० से अधिक पेपरलीकको घटनाएं होनेके बावजूद सरकारकी सेहतपर कोई असर नहीं दिखना हमारे विपक्षके मृतप्राय होनेका सन्देश देता है। आंकड़े बताते हैं कि अगस्त २०२६ में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ४.८२ फीसदी और १५ वर्षसे ऊपरकी बेरोजगारी दर पांच प्रतिशत थी। इसी अवधिमें युवा बेरोजगारी १५.१ फीसदी बतायी गयी है। ऐसेमें क्या विपक्षके नेता जनताकी समस्याओंको समझनेमें चूक कर रहे हैं, सुविधाभोगी हो गये हैं अथवा जनतासे उनका जुड़ाव नहीं रह गया है। तीन साल पहले १८ जुलाई २०२३ को बेंगलुरुमें विपक्षके २६ दलोंके नेताओंने इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्ल्युसिव एलायंस (इंडिया) के नामसे एक गठबंधन बनाया था। इसके शिल्पकार बिहारके तत्कालीन मुख्य मंत्री नीतीश कुमार थे। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टीके संयोजक अरविन्द केजरीवाल, राष्ट्रीय जनता दलके अध्यक्ष लालूप्रसाद यादव, समाजवादी पार्टीके मुखिया अखिलेश यादव, डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन, राष्ट्रवादी कांग्रेस (शरद) के अध्यक्ष शरद पवार, शिवसेना (उद्धव गुट) प्रमुख उद्धव बालासाहेब ठाकरे, झारखंड मुक्ति मोर्चाके अध्यक्ष हेमंत सोरेन, सीपीआईके डी. राजा, जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंसके फारूख अब्दुल्ला, पीडीपीकी महबूबा मुफ्ती और सीपीएमके सीताराम येचुरी समेत कई नेता शामिल थे। तय किया गया कि गठबंधनकी सभी पार्टियां आनेवाले दिनोंमें मिलकर चुनाव लड़ेंगी और विपक्षी वोटोंका बंटवारा रोकेंगी। लेकिन देशने देखा कि चुनावके समय सीटोंके बंटवारेपर गैर-भाजपा दलोंमें मतैक्य नहीं बन पाता है, इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी लगातार उठाते रही है। यह पहली बार नहीं है। डेढ़ दशक पहलेतक कांग्रेस भी यही करती रही थी। इंडिया गठबंधनके गठनके कुछ माह बाद ही चुनाव आयोग द्वारा राजस्थान, मध्यप्रदेश और छतीसगढ़के विधानसभा चुनावकी घोषणा की गयी। इसमें राजस्थान और छत्तीसगढ़में कांग्रेसकी सरकारें थीं और मध्यप्रदेशमें ज्योतिरादित्य सिंधियाके दलबदलके कारण सत्ता कांग्रेसके हाथसे फिसलकर भाजपाके पालेमें आ गयी थी। लेकिन इंडिया गठबंधनके दलों खासकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टीमें सीटोंपर सहमति नहीं बन पाने और प्रदेश कांग्रेस नेताओंके आपसी खींचतानके कारण तीनों राज्योंमें भाजपा अपने बूतेपर सरकार बनानेमें कामयाब रही। ज्ञात हो कि राजस्थानमें तबके मुख्य मंत्री अशोक गहलौत और पूर्व उपमुख्य मंत्री सचिन पायलट, छत्तीसगढ़में तबके मुख्य मंत्री भूपेश बघेल और तत्कालीन मंत्री टी. एस. सिंहदेवके आपसी विवादने कांग्रेसकी कामयाबीमें पलीता लगानेमें अहम रोल निभाया। इसी तरह मध्यप्रदेशमें कमलनाथ और दिग्विजय सिंहके बीच आतंरिक दरारके कारण कांग्रेस भाजपाके एंटी इनकंबेंसीका फायदा नहीं उठा सकी। यदि तब कांग्रेस दोनों दलोंको आठ-आठ सीटें भी दे देती तो बात नहीं बिगड़ती और गठबंधनकी एकता बनी रहती। उस समय कांग्रेस नेताओंने तर्क दिया कि गठबंधन लोकसभा चुनावके लिए है। शायद मतदाताओंको विपक्षके नेताओंकी यह बात नागवार गुजरी।

लोकसभा चुनावमें तो विपक्ष अधिकांश सीटोंपर मिलकर लड़ा। इसका फायदा भी उसे मिला। कांग्रेस पार्टी नेता विपक्ष के लायक सांसदोंकी संख्या (९९) जुटा पायी। बादमें हरियाणा, आंध्रप्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंडमें विधानसभाके चुनाव हुए। इसमें झारखंड एकमात्र राज्य रहा जहां हेमंत सोरेनकी सूझबूझसे गठबंधनके दलोंमें समन्वय हो पाया। वहां इंडिया गठबंधनको ५६ सीटें मिली। इससे वहां झामुमोकी अगुवाईमें सरकार भी बनी। बाकी राज्योंमें आपसी सहमति नहीं बन पानेके कारण इंडिया गठबंधनके दल धराशायी हो गये। बादके दिनोंमें दिल्ली, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरीमें भी गठबंधनके दलोंकी खूब दुर्गति हुई। पश्चिम बंगालमें तो ममताकी तृणमूल तीन धड़ोंमें बंट गयी। चुनाव आयोगने पार्टीके नाम और चुनाव चिह्नपर रोक लगा दी है। उधर हरियाणामें सीटें नहीं दिये जानेसे नाराज अरविन्द केजरीवाल इंडिया गठबंधनसे अलग हो गये और दिल्लीमें अकेले मैदानमें उतरे। नतीजतन सरकार तो गयी ही खुद चुनाव हारकर घर बैठ गये। तमिलनाडुके चुनाव परिणाममें किसीको बहुमत नहीं मिलनेकी स्थितिके कारण कांग्रेस और वाम दल सत्ताकी लालसामें विजयकी पार्टी टीवीकेके साथ चले गये। इससे नाराज स्टालिनने इंडिया गठबंधनसे अलग होनेका ऐलान कर दिया। लड़ाई बहुकोणीय होनेसे भाजपाको फायदा मिलता रहा है। कहनेका मतलब यह कि विपक्षकी एकजुटता दिखावटी है। ऐसेमें मन मिले बिना सिर्फ हाथ मिला लेनेसे मतदाता विपक्षी दलोंपर भरोसा करें तो कैसे करें।

उत्तर प्रदेशमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेसके दूसरी पंक्तिके नेताओंकी एक-दूसरेके खिलाफ बयानबाजीसे तो यही लगता है कि विपक्षके लिए दिल्ली अभी दूर है। पार्टीके बड़े नेताओंको इसमें दखल देना चाहिए और विवादको शांत कराना चाहिए। वोटके लिए एकजुट होकर जनताके पास जाना होगा। सपनेमें सरकार और कल्पनाका बालू बांटनेसे किसी दलका भला नहीं होगा। उधर असदुद्दीन ओवैसीकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मायावतीकी बहुजन समाज पार्टी पहलेसे विपक्षकी एकतामें पलीता लगा रही है। विपक्षी मतोंके विभाजनका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टीको मिल रहा है। ताजा मामला मुख्य चुनाव आयुक्तके विरोधका है। अंग्रेजीके एक अखबारमें चुनाव आयोगमें मतभेदकी खबरें और दो चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और डा. विवेक जोशीकी असहमतियोंको दरकिनार करनेसे उपजे हालातका है। विपक्षके लिए सरकारको घेरनेका यह बढ़िया मौका है। लेकिन इंडिया गठबंधनकी अगुवाई करने वाली कांग्रेस इस मुद्देका श्रेय अकेले ही लेना चाहती है। गठबंधनके बाकी दल अलग-थलग दिखाई दे रहे हैं। पटनामें तेजस्वीका अलग मोर्चा है तो दिल्लीमें केजरीवालकी अलग राह है। दरअसल क्षेत्रीय दलोंको मालूम है कि उनकी असली ताकत कांग्रेससे अलग हुए वोटरोंसे है। यदि कांग्रेस मजबूत हो गयी तो क्षेत्रीय दलोंका पुरसाहाल नहीं बचेगा। इसलिए वह भाजपाका विरोध तो करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेसको मजबूत करना नहीं चाहते। ऐसेमें देशकी सियासत किस करवट बैठेगी, समय बतायेगा।